from 1st August, 1991 to 29th February, 1992. It includes 5 letters of Intent granted in favour of Non-Resident Indians. Details such as name and address of the undertakings, locations, item (s) of manufacture and capacity in respect of Letters of Intent granted are published regularly by the Indian Investment Centre in their 'Monthly News Letter'. Copies of the publication are being sent to the Parliament Library regularly.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति

3919. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं दिए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान सरकारी क्षेत्र के किन-किन उद्योगों के कितने-कितने व्यक्ति स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए हैं और उन्हें कुल कितनी धनराशि का भुगतन किया गया है ?

उद्योग मंत्रयलय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सरकारी क्षेत्र के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी है, निम्नलिखित लाभों के पात्र हैं :—

(i) अंशदान भविष्य निधि विनियमों के अनुसार भुगतान योग्य उसके भविष्य निधि खाते की बकाया राशि ।

(ii) उद्यम के नियमों के अनुसार संचित अर्जित छुट्टी के बराबर नकद धनराशि ।

(iii) कर्मचारी पर लागू उपदान अधिनियम अथवा उपदान योजना के अनुसार उपदान धन राशि ।

(iv) एक माह/तीन माह का सूचना वेतन (उस पर लागू सेवा शर्तों के अनुसार) ।

(v) पूरे किये गये प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए $1\frac{1}{2}$ माह की परिलब्धियों (वेतन तथा महंगाई-भत्ता जोड़कर) के बराबर अनुग्रह राशि के भुगतान अथवा सेवा-निवृत्ति के समय मासिक परिलब्धियों को सामान्य सेवा-निवृत्ति की तारीख से पूर्व बची हुई सेवा के शेष महीनों से गुणा करके उसके बराबर राशि इनमें से जो भी कम हो ।

(vi) कर्मचारी और उसका परिवार पात्र श्रेणी से उस स्थान तक यात्रा करने का पात्र होगा जहां वह बसना चाहता है ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों के नाम तथा उन व्यक्तियों की संख्या, जिन्होंने गत छः महीनों के दौरान स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ली है तथा उन्हें अदा की गई कुल राशि के संबंध में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है । इसे एकत्रित किया जाएगा और सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

Negative growth rate in Engineering Industry

3920. SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether engineering industry has shown a negative growth rate ; if so, the extent thereof and the reasons therefor ; and

(b) the measures Government propose to take to check the same ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN) : (a) The Engineering Industry has recorded a decline of 6.5% during April-October 1991 over April-October 1990. The negative growth is due to various factors– infrastructural constraints, shortage of raw materials, particularly imported raw material because of foreign exchange constraints, credit squeeze, demand recession in the market, etc.

(b) Government has brought out a Statement on Industrial Policy which was tabled in the Lok Sabha on 24th July, 1991. The New Industrial Policy is aimed at improving industrial production by relaxing controls and removing bureaucratic delays. Many policy measures announced in the Union Budget for 1992-93 are designed to promote industrial growth. Thus, measures like partial

convertibility of rupee, reduction of duties on Capital Goods, would facilitate easier availability of raw materials, components etc. while measures like reduction in Statutory Liquidity Ratio and reduction in interest rate would facilitate easier availability of funds at lower cost for industrial development.

लोक उद्यम चयन बोर्ड में डेटा बैंक

3921. **श्रीमती सुषमा स्वराज्य :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक उद्यम चयन बोर्ड अपने कर्मचारियों के बारे में कोई डेटा बैंक रख रहा है ;

(ख) यदि हां; तो क्या यह प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है ;

(ग) इस डेटा बैंक में कितनी महिला प्रौद्योगिकीविदों को पंजीकृत किया गया था तथा बोर्ड स्तर के पदों के लिए कितनी महिला प्रौद्योगिकीविदों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और कितनों का चयन किया गया था ;

(घ) पुरुष सहयोगियों की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत कितना है ; और

(ङ) बोर्ड स्तर के शीर्ष पदों पर महिला प्रौद्योगिकीविदों का चयन करने संबंधी सरकार की भावी नीति क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) लोक उद्यम चयन बोर्ड केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोड स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के इच्छुक व्यक्तियों का एक डाटा बैंक रखता है । जब कभी भी आवश्यकता होती है तो इस डाटा बैंक का उपयोग विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त व्यक्ति ढूंढने के उद्देश्य से किया जाता है ।

(ग) से (ङ) : लोक उद्यम चयन बोर्ड महिला प्रौद्योगिकीविदों संबंधी कोई सूचना अलग से नहीं रखता है । सरकार की यह सुस्थापित नीति है कि बोर्ड स्तर के शीर्ष पदों पर जाति, लिंग अथवा धर्म आदि के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव के बिना एक स्वच्छ और उद्देश्यपूर्ण चयन प्रक्रिया के माध्यम से उत्कृष्ट व्यवसायिक प्रबन्धकों को नियुक्त किया जाए । सरकार इस नीति में कोई परिवर्तन करने पर विचार नहीं कर रही है ।

Discrimination of SC/ST employees in EPI

3922. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have recently received any Joint Representations from SC/ST Employees of EPI alleging violation of Government orders regarding reservations etc.; and

(b) if so, what action Government have taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. K. THUNGON) : (a) Yes, Sir.

(b) On the basis of information available with the Ministry, *prima facie*, it cannot be concluded that there is discrimination against SC/ST employees in EPI.

Export of vehicles by MUL to Yugoslavia

3923. SHRI VIREN J. SHAH : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the number of vehicles proposed to be exported by the Maruti Udyog Ltd. to Yugoslavia as per agreement signed between the two countries, upto the end of March, 1992 ;

(b) the number of vehicles exported so far to Yugoslavia ;

(c) the total number of Maruti vehicles Government propose to export upto March, 1992 ;

(d) whether there is a decline in scales of Maruti vehicles in the domastic market;

(e) if so, what is the expected sales and profits in 1991-92 as compared to the sales and profits in 1989-90 and 1990-91;

(f) the extent of the decline in sales and profits and what are the reasons therefor ; and